

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एक 6-7/05/अ-ग्यारह
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8/2/05

1. आयुक्त,
हाथकरघा एवं हस्तशिल्प
मण्डल भोपाल.
2. प्रबंध तंत्रालय,
मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम/मण्डल राज्य हाथकरघा हुनकर
सहकारी संघ, जबलपुर/मण्डल हाथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास
निगम, भोपाल/मण्डल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल/
मण्डल पाटलूम हुनकर सहकारी संघ, दुरहानपुर/मण्डल राज्य
सहकारी उपभोक्ता संघ भोपाल/मण्डल राज्य औद्योगिक सहकारी
संघ, भोपाल

विषय:- उद्योग संबर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना का क्रियान्वयन-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित वास्तविक उत्पादन इकाइयों के सम्बन्ध में।

उद्योग संबर्धन नीति-2004 एवं कार्य योजना को कंडिका क्रमांक 4.1.

5.12 विनियमन है:-

अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमियों को वर्तमान व्यवस्था में पूरा लाभ न मिल पाने के कारण इस वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित वास्तविक उत्पादन इकाइयों को शासकीय खरीदों कार्यक्रम में न्यूनतम 30 प्रतिशत को भागीदारों सुनिश्चित की जायेगी।

2/- मध्य प्रदेश झंडार कृषि नियम के नियम 14, 14 अ, 14 ब, 14 त, 14 द, एवं 14 इ, में शासकीय कृषि हेतु विभिन्न निगम/मण्डल/संस्थानों हेतु आरक्षण आरक्षित किये गये हैं। इन निगम/मण्डल/संस्थाओं द्वारा शासकीय कृषि हेतु आरक्षित आरक्षण शासकीय विभागों को प्रदाय किये जाते हैं।

3/- राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित वास्तविक उत्पादन इकाइयों को शासकीय खरीदों कार्यक्रम में न्यूनतम 30 प्रतिशत को भागीदारों सुनिश्चित

की जाय। अतः निर्देशित किया जाता है कि शासकीय धरोहर कार्यक्रम में न्यूनतम 30 प्रतिशत की धरोहर, वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्योगों द्वारा स्थापित वास्तविक उत्पादन इकाइयों से ही की जावें ताकि इतका पूरा लाभ इन वर्गों के उद्योगों को प्राप्त हो सके।

4/- उक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(विश्वपति सिन्हा)
विश्वपति सिन्हा

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

बागिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 8/2/05

संख्या 6-7/05/अ-ग्यारह

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल
 3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नवकारिता विभाग, भोपाल
 4. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
 5. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल
 6. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान दफ्तरी, मध्य प्रदेश भोपाल
 7. उद्योग आबुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
- को और सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वि. सिन्हा)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

बागिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग